

संक्षिप्त समाचार

स्वर्ण आभूषण के आपूर्तिकर्ता से लाखों रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में जौहरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

ठाणे, एजेंसी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने सोने के आभूषण की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति से 93.5 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक जौहरी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि आरोपी की शाहपुर क्षेत्र के खरदी में एक दुकान है और उसने पिछले तीन वर्षों में आपूर्तिकर्ता से 950 ग्राम सोने के आभूषण खरीदे हैं। कल्याण के बाजारपट्टे पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि कई बार याद दिलाने के बावजूद आरोपी ने आपूर्तिकर्ता को खरीदे गए सामान के लिए 93.5 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया। उन्होंने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने रविवार को आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2) (आपराधिक विधवांसघात) और 318(4) (धोखाधड़ी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

मणिपुर : दिलियाग व्यक्तिक की हत्या के आरोप में मेइती संगठन का एक नेता गिरफ्तार

इंफाल, एंजेसी। मणिपुर के इंफाल पश्चिम जिले में एक दिलियाग व्यक्तिक की हत्या कथित सलिसता के लिए मेइती संगठन अस्मबाई नेगोल (एटी) के एक नेता को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को एक बयान में बताया कि गिरफ्तार एटी नेता की पहचान युमनाम हुइइंग थियाम लीशांगखोंग निवासी लोंगजाम खाबा सिंह (35) के रूप में हुई है। वह पाओबिटेक मयाई लेकाई के मोहम्मद वेसम अब्दुल कादिर की हत्या का मुख्य आरोपी है। इसमें बताया गया है कि उसे रविवार को पुथिबा लाइंडुंग कॉम्प्लेक्स के पास मोंगसांगई माखा लीकाई अरुबाम लीकाई से गिरफ्तार किया गया है। बयान के अनुसार, अभी तक इस हत्या के संबंध में एटी के सात सदस्यों समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वेसम 11 जून की मध्यरात्रि को लापता हो गया था और बाद में उसका शव इंफाल पश्चिम जिले में समुरोऊ नाओरैम में मिला था, जहां उसे दफना दिया गया था। बयान में कहा गया है कि 17 जून को एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट, फोरेसिक टीम और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में शव को बाहर निकाला गया। इस हत्या के विरोध में प्रदर्शन हुए और इंफाल घाटी में कई मुस्लिम संगठनों ने इसकी निंदा की थी।

औवैसी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जमकर आलोचना की
 नईदिल्ली, एजेंसी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन औवैसी ने अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इजरायल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जमकर आलोचना की। औवैसी ने कहा कि अमेरिका के इस हमले से नेतन्याहू को फायदा हुआ है, जिन्हें उन्होंने फिलिस्तीनियों का कत्लाई करार दिया। औवैसी ने कहा, 'यह व्यक्ति फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है और वेस्ट बैंक व गाजा में जातीय सफाई कर रहा है। इतिहास उन्हें फिलिस्तीनियों के कत्साई के रूप में याद रखेगा।' भाूमू हो कि अमेरिका ने ईरान के नेताज, डेफ्हान और फोर्डों में परमाणु स्थलों पर हवाई हमले किए हैं। असदुद्दीन औवैसी ने पाकिस्तान की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की सिफारिश की भी कड़ी आलोचना की। लोकसभा सांसद औवैसी ने सवाल उठाया कि क्या पाकिस्तान ने ट्रंप का सम्मर्जन एक संभ्रम राष्ट्र पर बमबारी देखने के लिए किया था। उन्होंने रविवार को हैदराबाद में कहा, पाकिस्तानियों से पूछना चाहिए कि क्या इसके लिए वे ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान के आमी चीफ आसिम मुनीर ने इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ लंच किया था? आज इन सबकी पोल खुल गई है। हैदराबाद के सांसद औवैसी ने चेतावनी दी कि अगर इस क्षेत्र में पूर्ण पैमाने पर युद्ध छिड़ता है, तो भारत के लिए गंभीर नतीजे होंगे। उन्होंने कहा, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि खाड़ी और मध्य पूर्व में 1.6 करोड़ से अधिक भारतीय रहते हैं। अगर वहां युद्ध छिड़ता है, जो दुर्भाग्य से बहुत संभावित है, तो वहां रहने वाले भारतीयों पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय कंपनियों ने वहां भारी निवेश किया है और इस क्षेत्र से विदेशी निवेश का बड़ा हिस्सा आता है।

राजस्थान में जून में ही बारिश का बंपर बोनस, 24 जिलों में रिकॉर्ड टूटे

जयपुर, एजेसी। राजस्थान में इस बार मानसून की धमाकेदार एंट्री हुई है। 18 जून को प्रदेश में प्रवेश करने के बाद सिर्फ 5 दिन में ही मानसून ने जून महीने की औसत बारिश का कोटा पूरा कर दिया। अब तक (1 जून से 22 जून तक) राज्य में कुल 70.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि पूरे जून माह की औसत बारिश सामान्यतः 55 मिमी होती है। यह आंकड़ा साफ संकेत देता है कि इस बार प्रदेश में मानसून की रफ्तार तेज है। पिछले साल की तुलना में इस बार बेहतर बारिश दर्ज की गई है। जून 2024 में पूरे महीने में केवल 50.3 मिमी बारिश हुई थी, जो औसत से करीब 9 फीसदी कम थी। वहीं इस बार जून के तीसरे हफ्ते में ही राज्य औसत से काफी आगे निकल चुका है। जिलेवार आंकड़ों की बात करें तो 24 ऐसे जिले हैं जहां जून महीने की औसत बारिश से भी ज्यादा पानी अब तक बरस चुका है।

**कांग्रेस ने भारत सरकार से नैतिक साहस दिखाने को कहा,
जयराम रमेश बोले- अमेरिकी बमबारी की निंदा करे पीएम मोदी**



की ताकत का इस्तेमाल करने का राष्ट्रपति ट्रंप का गिनियम ईरान के साथ बातचीत जारी रखने के उद्देश्य के अलावा का मजाक है। उन्होंने कहा कि काप्रेस, ईरान के साथ तत्काल कूटनीति और बातचीत की अनिवार्यता को दोहराती है। काप्रेस नेता ने कहा, भारत सरकार को अब तक की तुलना में अधिक नैतिक साहस का प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने दावा किया, मोदी सरकार ने स्पष्ट रूप से अमेरिकी बमबारी और इजराइल की आक्रामकता, बमबारी और लक्षित हत्याओं की न तो आलोचना की है और न ही निंदा की है। इसने गाजा में फ़लस्तीनियों पर किए गए दस नरसंहार की भी चुप्पी साध रखी है। इससे पहले, काप्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने बीते शनिवार को आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने गाजा की स्थिति और इजराइल-ईरान सैन्य संघर्ष पर चुप्पी साधते हुए भारत के सैद्धांतिक रब और मूल्यों को त्याग दिया है। उन्होंने यह भी

कहा था कि सरकार को आवाज बुलंद करनी चाहिए और पश्चिम एशिया में संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए उपलब्ध हर राजनयिक मंच का उपयोग करना चाहिए। काग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने अंग्रेजी दैनिक "द हिन्दू" में भारत के एक लेख में यह कहते हुए कहा कि लंबे समय से मित्र रहा है और गहरे सभ्यतागत संबंधों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसका जम्मु-कश्मीर समेत महत्वपूर्ण मौकों पर दृढ़ संधन का इतिहास रहा है।" उन्होंने उल्लेख किया कि वर्ष 1994 में ईरान ने कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत की आलोचना करने वाले एक प्रस्ताव को रोकने में मदद की थी।

काँग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा, "वास्तव में, इस्लामी गणतंत्र ईरान अपने प्रगतिशील, ईरान के 'शाह शासक' की तुलना में भारत के साथ कहीं अधिक सहयोगी रहा है, जिसका झुकाव 1965 और 1971 के युद्धों में पाकिस्तान की ओर था।" सोनिया गांधी का कहना है, झलक के दशकों में भारत और इराक़ के बीच भी दशकों का संबंध विकसित हुए हैं। इस महत्वपूर्ण स्थिति में आने से हमारे देश का तनाव कम करने और शांति बहाल करने का नैतिक दायित्व और शक्ति बढ़ी है। यह कौनो कोरा सिद्धांत नहीं है। पश्चिम एशिया में लाखों भारतीय नागरिक रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, इसलिए इस क्षेत्र में शांति स्थापना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा है।

सपा ने भाजपा के पाले में गए 3 विधायकों को पार्टी से निकाला, कहा-जहां रहें, विश्वसनीय रहें

लखनऊ, एप्रैल। समाजवादी पार्टी ने लंबे अरसे से भाजपा के पाले में नजर आ रहे उसी जमाने की तीन विधायकों को औपचारिक तौर पर पार्टी से निकाल दिया है। इन विधायकों के नाम हैं मनोज पांडेय, अनुर सिंह और राकेश प्रसाद सिंह। पार्टी के अधिकारिक एक्स आर्टिकल में इसकी जानकारी दी गई है। सपा ने कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोपों में इन्हें निकाला जा रहा है। इसके साथ ही पोस्ट के अंत में तंज करते हुए लिखा गया है- जहाँ रहें, विश्वसनीय रहें। बता दें कि पिछले साल राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा के तीन विधायकों ने भाजपा का सपा दिया था।

2024 के छठवीं महीने में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने 8 और सपा ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। कौंस वॉटिंग करने वाले में नीतीश जीन सीट से विधायक राकेश प्रसाद सिंह, गोसावईजीन सीट से विधायक राकेश सिंह और ऊयासर सीट से विधायक मनोज कुमार पांडेय शामिल थे। समाजवादी पार्टी के एक एक्स आर्टिकल पर विधायकों के निष्काशन की सूचना देते हुए लिखा गया है- "समाजवादी सोलडरूप सरकारमक विचारधारा की राजनीति के विपरीत साम्प्रदायिक विषयजनकारी जनकारिताकरता व किसान, महिला, युवा, कारोबारी, नौकरिपेशा और 'पीडी विरोधी' विचारधारा का साथ देने के कारण, समाजवादी पार्टी जनहित में निम्नांकित विधायकों को पार्टी से निष्काशन करती है।

हिंदू होने पर ही आपत्ति क्यों? अपमान
मत करो, फेक सेवयुलरिज्म पर
भड़के पवन कल्याण

मार्तुरी, एजसे। आंध्र प्रदेश के उन्मुख्यमंजी और जसनेना
 हिंदू के प्रमुख पवन कल्याण ने रविचार को तमिलनाडु के
 तदुदुरे में आयातित 'मुगल भक्तगणित मण्डल' (भावाना
 मण्डल) के भक्तों का सम्मेलन) में फेक सेवक्युलरिज्म और
 हिंदु धर्म पर एकतरफा निशानेबाजी को लेकर तीव्रता हमला
 किया। उन्होंने कहा कि : 'उत्पादी नहीं, प्रतिबद्ध हिंदू ही'
 'हिंदू होने पर ही आपसित वय्यां : पवन कल्याण ने
 कहा, 'एक ईसाई को ईसाई बने रहने में, एक मुसलमान को
 मुसलमान बने रहने में किसी को समझना नहीं होता, लेकिन
 जैसे ही कोई हिंदू अपने धर्म को लेकर प्रतिबद्ध होता है, उसे
 'सांप्रदायिक' करार दे दिया जाता है। यही इनका फेक
 'साम्प्रदायिक' है।' उन्होंने आगे कहा, 'अभिव्यक्ति को
 वय्यवत्रता हमारे सविधान ने दी है, लेकिन अब इसका
 प्रयोग सिर्फ हिंदू देवी-देवताओं का मानक उठाने के लिए
 किया जा रहा है। यह बंद होना चाहिए, वरना हमारे धर्म
 और आस्था को टिकाए रहना मुश्किल हो जाएगा।

इस्लाम और ईसाई धर्म का सम्मान : पवन कल्याण ने अपने भाषण में साफ कहा, «मैं इस्लाम और ईसाई धर्म का भी उतना ही सम्मान करता हूँ, जितना अपने धर्म का। लेकिन मेरी भी एक ही गुज़ारिश है - मेरे धर्म का अपमान मत करो। आप मेरी आस्था का सम्मान न करो, पर उसका अपमान भी मत करो।»

मुरुगन पूरे भारत में पूजनीय : पवन कल्याण ने अपने संबोधन में भगवान मुरुगन को लेकर कहा कि वे अपने प्रतिमिलाडु तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनर भारत में नातिक्रिये, आंध्र और कर्नाटक में सुब्रह्मण्यम के रूप में पूजे जाते हैं। उन्होंने सब बात पर दुख भी जताया कि कुछ साल पहले 'कंड छप कवचम' जैसे धार्मिक स्तुति गीत का एक अलग ही कल्याण रूप से मजाक उड़ गया था। पवन कल्याण ने आगाह करते हुए कहा, 'हिंदुओं की सहनशीलता को उनकी कमजोरी न समझा जाए। अगर बार-बार उकसाया जाय, तो जवाब भी मिलेगा। धर्म की रक्षा हर भक्त का दायित्व है। सम्मेलन में भाजपा नेता के, अन्नामलाई, हिंदु मनुनाई प्रमुख कादेश्वर सुब्रमणियम, द्रष्टव्य के नेता और मंत्री भी शामिल हुए। अन्नामलाई ने कहा कि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि हिंदुओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता का मंच है।

राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक
फेरबदल, सरकार ने 62 आईएएस
अधिकारियों के तबादले किए

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान सरकार ने नौकरशाही में बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 62 अधिकारियों के तबादले किए। कार्मिक विभाग ने रविवार देर रात तबादला सूची जारी की। इसके तहत आठ अतिरिक्त मुख्य सचिवों और 11 जिला अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। साथ ही 21 आईएएस अधिकारियों को विभागों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कार्मिक विभाग ने रविवार देर रात तबादला सूची जारी की। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अखिल आरड़ा को करीब पांच साल बाद वित्त विभाग से स्थानांतरित कर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचडीटी) में एसीएस नियुक्त किया गया है।

राजस्थान सरकार ने 62 आईएसएम अधिकारियों के तबादले किए: आधिकारिक आदेश के अनुसार श्वेता चौहान को फ्लोटीदा का नया जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वे इससे पहले स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) को निदेशक के पद पर कार्यरत थीं। फ्लोटीदा कलेक्टर हजोजिला अदल को राज्य स्वास्थ्य बीमा एजेंसी का सीईओ लगाया गया है। इसी तरह जोधपुर जिला परिषद के सीईओ डॉ. धीरज कुमार सिंह को कार्मिक विभाग में सरकार का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

हरियाणा में ऐसा खौफ कि शराब कारोबार से ही तौबा, 5 बार फेल हुई नीलामी, सीएम को बुलानी पड़ी मीटिंग



चंडीगढ़, एजेंसी। दारू और बाबू यानी बालू के ठेकों को अच्छी कमाई का जरिया माना जाता रहा है। किसी भी राज्य में शराब के ठेकों के लिए बोली लगाने का होड़ा रहती है और इसकी वजह इनसे होने वाली मोटी कमाई है। लेकिन हरियाणा में लोग शराब के ठेकों के लिए बोली ही नहीं लगा रहे हैं। इसकी कई वजहें हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण इस धंधे में गैंगस्टरों का शामिल होना है। इसके चलते कोई भी ऐसा व्यक्ति इस धंधे के लिए बोली नहीं लगा सकता है, जो बाहुबली न हो और क्राइम से उसका वास्ता न हो। हरियाणा में सरकार के लिए शराब उद्योग से मिलने वाला रोज़ेन्यू विकास और गरीब कल्याण की नीतियां बनाने में काम आता

रहा है। नायब सिंह सैनी सरकार के लिए चिंता की बात यह है कि प्रदेश के 22 जिलों में से 20 ऐसे हैं, जहाँ शराब के ठेकों के लिए कोई बोली ही नहीं लगी है। 5 बार अन्तर्नाइन नीलामी का विज्ञापन जारी किया जा चुका है, लेकिन कोई भी बोली लगाने के लिए आए नहीं आ रहा। बड़ी बात यह है कि नई सरकार से कुड़कानों तो गुराग्रह, फरीदाबाद, पंचकूला और यमुनानगर में हैं। इन शहरों की शराब दुकानों को अच्छे कमाई वाला माना जाता है। फिर भी यहां की दुकानें बोली का इंतजार कर रही हैं। अब तक किसी के लिए भी इन दुकानों का आवंटन नहीं हो सका है। दरअसल कुश्कर्ष में 13 जून को एक शराब कारोबारी की हत्या हो गई थी। उसके बाद से पूरे



देश में ही डर और बढ़ गया है। राबत और यमुनानगर में भी लोगों के ठेकों के लिए बोली गाने के इच्छुक कुछ लोगों को कमियां दी गई हैं। हालात यह है कि सीएम नायब सिंह सेनी ने खुद राबत कारोबारियों की एक मीटिंग बुलाई। इस बैठक में उन्होंने लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया और हरिय

लोग डरें नहीं। हम किसी बड़े सिंडिकेट या फिन्स के अलग-अलग माहौल में एक-एक करके मिलकर अचला उन्होंने भी आदेश दिया कि मैं पर सख्त ऐक्शन करूँ के लिए बोली कि कोई यदि उन पर कार्रवाई की जा में हमेशा से ही का कारोबार दबंगों रहा है। इसमें कोई शमिल नहीं होना कारोबार में बड़े पैसा और धमकियाँ हैं। लेकिन इस बार ज्यादा खराब है। तब साथ ही आबकारी अधिकारियों तक को देने सामने आ रहे हैं। शराब का कारोबार

किसी बड़े सिंडिकेट या फिन्स के माध्यम से नहीं चलता। इसकी बजाय यही ऑनलाइन बोली लगती है लेकिन इस बार धमकियों के चलते लोग बोली लगाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।

भाजपा सरकार ने बढ़ाया आबकारी विभाग से रेवेन्यू टारगेट : बता दें कि मौजूदा वित्त वर्ष में हरियाणा की भाजपा सरकार ने आबकारी विभाग से ही 14,063 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जुटाने का लक्ष्य तय किया है। इससे पहले बोली वित्त वर्ष में यहाँ 11,054 करोड़ रुपये ही था। अब तक करीब 260 ज़ोन ऐसे हैं जहाँ बोली नहीं लगी है और इनसे ही करीब 4000 करोड़ के रेवेन्यू की उम्मीद है।

**तालाब की खुदाई के दौरान निकलने लगे नरककाल,
एक तो 8 फीट लंबा; मिलीं अजीब चीजें**



जौद, एजेंसी। हरियाणा के जौद जिले के जुलाना के गांव देवदंड में रविवार को मनरेगा योजना के तहत चले रही तालाब की खुदाई के दौरान 10 नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। एक कंकाल की लंबाई 8 फुट के आसपास है, जो सामान्य मानव कंकाल से अधिक है। इसके साथ ही मिट्टी से निकले जबड़े और अन्य हड्डियां आम इंसान के शरीर से कहीं बड़ी बताई जा रही है। खुदाई में कुछ टूटे-फूटे मटके और मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, जिससे पता चलता है।

एक के बाद एक नर कंकाल मिलते गए : गांव देवरड़ मनरोजा के तहत दो महीने से तालाब का खुदाई का काम जारी था, जिसमें रोजाना 50 से 60 मजदूर लगे हुए थे। रविवार को खुदाई के दौरान एक नर कंकाल मिला जिससे मजदूर डर गए। आनन-फानन में उन्हीने सरपंच को मामले की जानकारी दी। इसके बाद जीडीपीओ को सूचित किया गया। जैसे-जैसे मजदूर खुदाई करते गए, एक के बाद एक नर कंकाल मिलते गए। कुल 10 नर कंकाल मिले और पुराने युग

निकल। हरिना को बात यह कि ये सभी नर कंकालों की लंबाई सामान्य इंसान की लंबाई से कहीं अधिक थी। हड्डियों की लंबाई भी ज्यादा थी।

खुदाई का काम रोका, पुरातत्व विभाग की मदद लेंगे: बीडीपीओ : जुलाना के बीडीपीओ प्रतीक जांगड़ा ने बताया कि खुदाई के दौरान कंकाल मिलने की सूचना पर काम को तत्काल रोक दिया गया है और जांच टीम को मौके पर भेजा गया है। जांच के बाद ही आगे की खुदाई का निर्णय लिया जाएगा। इन कंकालों की

आर वज्रानां का मदेल ला जाएणा, ताका
यह पात्र लख सके कि यह मानव अवशेष
किफ कारखंड से संबंधित है अथवा इन्की
असामान्य लंबाई का रहस्य क्या है।
सुनियोजित तरीके से दफनाए गए
शव लगे: वहीं, मजदूरों और ग्रामीणों
का दावा है कि जिस दास से हड़िया दबी
थी, उससे लगता है कि ये सुनियोजित
तरीके से दफनाए गए शव हैं। गांव के
बुजुर्गों ने बताया कि आजादी से पहले इस
जगह पर मुस्लिम समुदाय का कब्रिस्तान
होता करता था।

उत्तर भारत में पहुँचा मॉनसून, बाकी देश में 30 जून तक होगी बारिश

नईदिल्ली, एजेंसी। मौनसून को लेकर अच्छी खबर है। मौसम विभाग आगे कुछ दिनों में अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहा है। मौनसून लगभग पूरे उत्तर भारत को कवच चुका है। उत्तर अरब सागर में अभी हलाल इस्को के अनुकूल बने हुए हैं। अब मौनसून, राजस्थान के और अधिक हिस्सों, हरियाणा के कुछ हिस्सों, चंडीगढ़ और दिल्ली तक भी पहुँचने वाला है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आगे दो दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बचे हुए हिस्सों, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तक भी मौनसून पहुँच जाएगा। रविवार तक, मौनसून हिमाचल प्रदेश और जम्मू के अधिकांश हिस्सों, पर लद्दाख और

शमीर, और पंजाब के कुछ हिस्सों में
गे बढ़ा, जबकि उत्तर-पश्चिमी
न्यों हरियाणा और दिल्ली को छोड़
या। मॉनसून की उत्तरी सीमा अब
पपुर, आगरा, रामपुर, देहरादून,
मला, पठानकोट और जम्मू के
ध्यम से गुजर रही है।

यह अच्छा संकेत : आईएमडी
डायरेक्टर जनरल एम मोहपात्रा ने
बताया कि मॉनसून ने उत्तर भारत के
धार्मिकाश हिस्से को थोड़ी जल्दी
धर किया है। लेकिन हमने अभी
क पूरे देश के कवरेज के लिए
मॉनसून नहीं दिया है। पंजाब,
याणा, दिल्ली और राजस्थान के
छ हिस्से भी अभी कवर होने बाकी
उन्होंने आगे बताया कि हम उम्मीद



कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में इन राज्यों तक भी मॉनसून की पहुंच होगी। हम अगले कुछ दिनों में अच्छी

बारिश की उम्मीद कर रहे हैं। खासतौर पर दक्षिण उत्तर प्रदेश और गंगीय पश्चिम बंगाल के ऊपर एक निम्न

दबाव क्षेत्र के कारण ऐसे हालात बन रहे हैं। यह विशेषताएं मॉनसून के लिए अच्छी हैं।

एसाँ रही मानसून की यात्रा :
सामान्यतः, 15 जून तक, मानसून
दक्षिण समेत महाराष्ट्र के अधिकांश
हिस्सों, तेलंगाना के बाकी क्षेत्रों,
दक्षिण छत्तीसगढ़, मध्य भारत के
बाकी क्षेत्रों, ओडिशा के अधिकांश
क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के अधिकांश
हिस्सों, सिक्किम और बिहार और
झारखंड के कुछ पूर्वी क्षेत्रों तक रहता
है। इसके बाद वह गुजरात और कच्छ
के दक्षिणी हिस्सों, महाराष्ट्र के बाकी
हिस्सों, दक्षिण मध्य प्रदेश, ओडिशा के
बाकी हिस्सों, और 20 जून तक उत्तर
छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के

अधिकांश हिस्सों की तरफ बढ़ जाता है। इसके बाद मॉनसून उत्तर और पश्चिम की ओर आगे बढ़ता है। फिर 15 जून 30 जून तक गुजरात और कच्छ, पश्चिम प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, नदाख, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों को कवर करता है। यह 8 जुलाई तक उत्तर-पश्चिम भारत के शेष क्षेत्रों में पहुंचता है।

समय से पहले पहुंचा इस साल ऑनसून अपेक्षा से पहले ही विभिन्न क्षेत्रों में पहुंच गया है। इसका अभी तक रास्ता बहुत असामान्य रहा है। ऑनसून ने 24 मई को केरल में आठ दिन पहले दस्तक दी।

घर पर वर्षों से आराम फरमाते मारसाब, भौकाल इतना कि खाते में वेतन पँहुचे बेहिसाब

पन्ना । शाहनगर विकासखण्ड अन्तर्गत वेतन घोटाले का मामला प्रकाश में आया है जिसमें शासकीय हाईस्कूल मैन्हा में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक बाल्मीक बागरी सन् 2019 से वर्तमान तक जनपद शिक्षा केन्द्र गुनौर में विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है, किन्तु साहेब का भौकाल इतना है कि साहेब ना गुनौर में कार्यरत है और नाहि मैन्हा में, किन्तु महगाई के दौर में वेतन बेधड़क साहेब के खातें में वर्षों से डाली जा रही है। मामले की पड़ताल करने पर पता चला कि पूर्व प्रभारी प्राचार्य मैन्हा सुशील श्रीवास्तव, सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी शाहनगर कमल सिंह व प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी रागिनी तिवारी की चैकड़ी द्वारा आपस में हितलाभ साधते हुए यह खेल रचा गया, आपस में क्या समझौता या लेनदेन था यह अब भी रहस्यमयी बना हुआ है। मामले का खुलासा सूचना के अधिकार 2005 के तहत



जानकारी प्राप्त हाने पर हुआ, जिसमें शिकायतकर्ता ने पाया कि संबंधीजन को बगैर उपस्थिति के इन तीनों के द्वारा वेतन हितलाभ घर बैठे अनवरत बेरोकटोक पहुँचाया जा रहा था। जनपद शिक्षा केन्द्र गुनौर बीआरसीसी गणेश शंकर शर्मा ने बताया कि जनपद शिक्षा केन्द्र गुनौर की उपस्थिति पंजी में संबंधीजन के कई सालों से हस्ताक्षर है ही नहीं, बाल्मीक बागरी बगैर सूचना के अनुपस्थित है, और नाहि अभी तक कार्यालय से मुक्त हुए है, वा नाहि मेरे

बिल लगाकर लिपिक द्वारा डीडीओ विकासखण्ड शाहनगर भेजकर संबंधीजन को वेतन भुगतान की जाती रही है, जो आज भी लगातार जारी है, चूँकि शिकायकर्ता द्वारा उक्त मामला मेरे संज्ञान में लाया गया है, जिस पर वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशन में कार्यवाही की जावेगी तथा कार्यालय में पदस्थ दोनों लिपिकों वा संबंधीजन को कारण बताओं सूचना पत्र भी जारी किए गए हैं। उक्त मामले में शिकायतकर्ता द्वारा वरिष्ठ कार्यालयों में शिकायती आवेदन देकर संबंधित दोषियों के विरुद्ध आहरित वेतन की वसूली वा कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की माँग की गई है तथा जब तक दोषियों के विरुद्ध जाँच जारी रहे उन्हें निर्लंबित रखा जावे ताकि जाँच निष्पक्ष हो सके।

इनका कहना है

पूर्व प्राचार्य सुशील श्रीवास्तव मैन्हा द्वारा संबंधीजन को अनवरत वेतन भुगतान की जाती रही है, मामला संज्ञान में आने के बाद वेतन भुगतान के

एडवोकेट अंकित शर्मा के साथ पार्षद पति रवि पांडे ने की मारपीट कोतवाली थाना में मामला दर्ज

पन्ना । एडवोकेट तथा कांग्रेस नेता अंकित शर्मा ने कोतवाली पन्ना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि मैं दिनांक 20 जून को रात्रि लगभग 10:45 बजे कड़ा पान भंडार पर खड़ा था तथा पान खाकर घर जाने वाला था इस दौरान नगर पालिका वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद के पति रवि पांडे पिता राम भुवन पांडे आए एवं बिना किसी कारण के बहस करने लगे एवं गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई लोगों द्वारा बीच बचाव किया गया उसके द्वारा दोबारा फिर से बाल्टी उठाकर मारपीट करने का प्रयास किया गया एवं जान से मारने की धमकी दी गई जिसकी शिकायत अंकित शर्मा द्वारा कोतवाली पुलिस ने 21 जून को,, संबंधित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है जिसमें धारा 115 296, 351 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है ज्ञात हो नगर पालिका पन्ना में पतियों का बोलबाला है अध्यक्ष पति पार्षद पति आदि नगर पालिका का संचालन कर रहे हैं क्योंकि नगर पालिका पन्ना में दो दर्जन से अधिक महिलाएं पार्षद बनी हैं लेकिन महिलाओं के स्थान पर पतियों द्वारा ही कार्य किया जा रहा है तथा उनकी दबंगई नगर पालिका में चल रही है बताया जाता है कि अंकित शर्मा द्वारा नगर पालिका में लगातार हो रहे

बिजली की आंख मिचौली, तथा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही से आम जनता परेशान

पन्ना । वर्तमान समय में बिजली विभाग की लापरवाही से आम जनता भारी परेशान है लगातार अधोषित बिजली कटौती एवं बिजली आंख मिचौली से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है क्योंकि वर्तमान समय में भारी गर्मी एवं उमस होने के कारण बिना कूलर पंखा के लोगों का उठना बैठना सोना मुश्किल है साथ ही इस मौसम में जहरीले कीड़े साँप बिच्छू आदि निकलते हैं जो लोगों को हानि पहुंचते हैं तथा आए दिन दुर्घटना घटित हो रही है भारी भरकम बिजली बिल देने के बावजूद व्यवस्था में बेहतर सुधार नहीं है ग्रामीण क्षेत्र की बात अलग है जिला मुख्यालय की भी यही स्थिति है लोगों द्वारा बताया गया यदि किसी कारणवश बिजली व्यवस्था बिगड़ जाती है विद्युत मंडल कार्यालय फोन लगाओ कोई उठाता नहीं है यदि कोई कर्मचारी फोन उठाता है तो वह कहता है कि हमारे पास अभी स्ट्राफ नहीं है प्राइवेट कर्मचारियों से काम कर लो इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है कनिष्ठ यंत्री राहुल बिरला कार्यप्रणाली भी जनहित कारी नहीं है जिससे आम जनता की समस्या में सुधार हो सके।

जिला स्तरीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम 25 जून को

पन्ना । गृह विभाग के आपदा प्रबंधन संस्थान के निर्देशानुसार जेंडर संवेदनशीलता एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर जिला प्रशासन के समन्वय एवं यूएन वीमेन इंडिया के तत्वाधान में बुधवार, 25 जून को सुबह 10.30 बजे से शाम 4 बजे तक मड़ला के एमपीटी होटल में जिला स्तरीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिला कलेक्टर ने एक दिवसीय कार्यक्रम के लिए संयुक्त कलेक्टर कुशल सिंह गौतम को नोडल अधिकारी

बनाया है, जबकि संबंधित विभागीय अधिकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा भी आवश्यक सहयोग व समन्वय किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि आपदा प्रबंधन की तैयारी एवं प्रतिक्रिया प्रणालियों में जेंडर समानता, सामुदायिक लचीलापन एवं विभागीय समन्वय की प्राथमिकता अनुसार गत दिवस राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ था। इस क्रम में स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों एवं संवेदनशील

पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ रामकृष्ण कुसमरिया 24 जून को पन्ना आएंगे

पन्ना । मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया मंगलवार, 24 जून को सुबह 8 बजे सकौर से प्रस्थान कर पन्ना आएंगे। आयोग अध्यक्ष डॉ. कुसमरिया 11 बजे पन्ना में पिछड़ा वर्ग छात्रवासों का निरीक्षण कर दोपहर 3 बजे कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे एवं शाम 5 बजे छतरपुर रवाना होंगे।

विद्यालयों की मान्यताओं में लंबा खेल, जिला शिक्षा केंद्र में मोटी रकम लेकर जारी की गई मान्यताएं

पन्ना । जिले में निजी स्कूलों को मान्यता जारी करने में जिला शिक्षा केंद्र द्वारा जमकर वसूली करने का मामला सामने आया है अनेक विद्यालयों की जांच अधीनस्थ अमला के द्वारा टीम बनाकर कराई गई जिसमें भारी अनियमितताएं सामने आई थीं तथा संबंधित जांच टीम द्वारा मान्यता न देने की अनुशंसा की गई थी लेकिन जिला शिक्षा केंद्र कार्यालय द्वारा टीम की टीप को दर किनार करते हुए मनमानेढंग मान्यता जारी कर दी गई तथा पूरे जिले के निजी विद्यालयों से भारी वसूली की गई तथा सारे नियम कानून जांच टीमों की रिपोर्ट दरकिनार करते हुए फोलगुड होते ही सभी कमियां दर किनार करते हुए मान्यताएं फटाफट जारी कर दीं हैं। इसी प्रकार का मामला देवेंद्र नगर का सामने आया है जहां पर बड़ा गांव स्थित मिलेनियम पब्लिक स्कूल की जांच जिला शिक्षा केंद्र द्वारा कराई गई थी जिसमें जांच टीम द्वारा तीन बिंदुओं को लेकर मान्यता जारी न करने की रिपोर्ट दी गई थी लेकिन उसके

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित

पन्ना । महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पन्ना जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त 13 पद एवं सहायिका के 328 रिक्त पद पर भर्ती के लिए एमपी ऑनलाइन द्वारा तैयार चयन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विगत 20 जून से आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ है। महिला आवेदकों द्वारा पोर्टल पर आगामी 4 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, जबकि आवेदन में संशोधन की तिथि 7 जुलाई निर्धारित है। जिला कार्यक्रम अधिकारी अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि परियोजना अजयगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के क्रमशः 3 एवं 85, गुनौर में 2 एवं 51, पन्ना ग्रामीण में 3 एवं 73, पवई में 1 एवं 65 तथा शाहनगर में कार्यकर्ता के 4 एवं सहायिका के रिक्त 49 पद पर भर्ती की जाना है, जबकि पन्ना शहरी परियोजना अंतर्गत कार्यकर्ता के एक भी पद रिक्त नहीं हैं, केवल वार्डवार आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त सहायिका के 5 पद पर भर्ती की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता, आयु एवं अन्य नियम निर्देशों की जानकारी के लिए पोर्टल का अवलोकन किया जा सकता है। कार्यालयीन दिवस एवं समय पर कलेक्ट्रेट स्थित जिला कार्यक्रम अधिकारी अथवा परियोजना कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।

पड़ोसी ने महिला को बेरहमी से पीटा, फिर घर में किया बंद, तमाशा देखते रहे लोग

सतना । मैहर कोतवाली क्षेत्र के वार्ड 21 गोविंदनगर में सनसनीखेज घटना सामने आई। एक युवक ने पड़ोस में रहने वाली महिला को अकेला पाकर उसके घर में घुसकर मारपीट की और फिर बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। पीड़ित महिला हीराबाई शुक्ला (56) करीब दो घंटे तक कमरे में बंद रही।

जानकारी के अनुसार, सुबह 5 बजे आरोपी संतोष खीमर महिला के घर में घुसा, उसके साथ मारपीट की और धमकी देते हुए बाहर से ताला लगाकर चला गया। भागते समय उसने पड़ोसियों को

आवेदनों का समय सीमा में निराकरण नहीं होने पर नोटिस जारी

पन्ना । लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंधित आवेदनों का समय सीमा में निराकरण नहीं होने पर तीन ग्राम पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनमें पवई विकासखण्ड की ग्राम पंचायत रैकरा, पन्ना विकासखण्ड की ग्राम पंचायत गौरा एवं अजयगढ़ विकासखण्ड की ग्राम पंचायत मोहाना के सचिव शामिल हैं।

जिला योजना अधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी लोक सेवा गारंटी अल्ट्रा रजनी दास द्वारा अधिनियम की धारा 5(2) के उल्लंघन पर धारा 6 के तहत स्वप्रेरणा के आधार पर संज्ञान लेकर नोटिस जारी करने की कार्रवाई की गई है। इस संबंध में तीन दिवस के भीतर संबंधित सचिव से अधिनियम के 7.1 (क) के प्रावधान अनुसार 500 रूपए प्रति आवेदन के मान से शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में प्रतिवेदन चाहा गया है। जबाब संतुष्टिपूर्ण न होने एवं भविष्य में समय सीमा बाधा संबंधित आवेदन पाए जाने पर एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।

प्रेक्षक से कर सकते हैं संपर्क

पन्ना । राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर परिषद ककरहटी के वार्ड क्रमांक 13 में पार्षद पद के उप निर्वाचन के लिए नियुक्त प्रेक्षक राजा सिंह परिहार पन्ना पहुंच गए हैं। प्रेक्षक श्री परिहार सफिंट हाउस पन्ना में ठहरे हैं। उप चुनाव के संबंध में कोई भी व्यक्ति अथवा दल के प्रतिनिधि सफिंट हाउस में प्रेक्षक से संपर्क कर सकते हैं। प्रेक्षक के मोबाइल नंबर 9406621016 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

अतिक्रमण की चपेट में 17 स्मारक

सतना । सतना जिले में राज्य संरक्षित पुरातात्विक स्मारकों पर अतिक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। दूर-दराज इलाकों में स्थित होने और जनता से सीधा जुड़ाव न होने के कारण इन स्मारकों पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय ने सतना कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस को अवगत कराया है, जिसके बाद कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को स्मारकों की सूची सहित अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। पुरातत्व संचालनालय को विभिन्न जिलों से स्मारकों पर अतिक्रमण की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। ऐसा ही एक मामला टीकमगढ़ जिले में सामने आया था, जहां आरतीन की गद्दी के पहुंच मार्ग पर लोगों ने दीवार बना दी थी, जिससे स्मारक का अनुक्षण और विनाश कार्य रुक गया था। संचालनालय ने तुरंत टीकमगढ़



कलेक्टर विवेक श्रीतीव को इसकी जानकारी दी, जिन्होंने तत्काल अतिक्रमण हटवा दिया। इस घटना का उदाहरण देते हुए सचिव संस्कृति आयुक्त उमिला शुक्ला ने सतना कलेक्टर को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विरासत स्थलों के संरक्षण के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं। उन्होंने जोर दिया कि पुरातत्व संचालनालय के तहत आने वाले स्मारक हमारी समृद्ध विरासत की

रक्षा के लिए हैं और उनकी सुरक्षा हमारा संवैधानिक दायित्व है। सचिव शुक्ला ने सतना के पुरातात्विक स्मारकों की सूची के साथ बताया कि इनमें से कई स्मारकों पर स्थानीय स्तर पर अतिक्रमण हो चुका है। लिहाजा, उन्होंने कलेक्टर को सभी स्मारकों का सर्वे कराकर टीकमगढ़ कलेक्टर को तब पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सचिव संस्कृति आयुक्त उमिला शुक्ला ने जिले में स्थित 17



थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को जांच में सामने आया कि कार संजय साकेत के नाम पर फाइनेंस कराई गई थी जो पूजा मिश्रा के पेट्रोल पंप पर कर्मचारी था, जिसे वह अमरपाटन में किराए पर चलाती है। आरोपियों ने संजय के दस्तावेजों का चोरी-छिपे

इस्तेमाल कर कार फाइनेंस करा ली थी। मैहर पुलिस ने इस मामले में डेढ़ महीने पहले पूजा के एक भाई विपिन तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दूसरा फरार आरोपी विवेक तिवारी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पूजा से आगे की पृष्ठताछ की जा रही है। पुलिस को ये भी पता चला है कि सौदा और लिखापट्टी के दौरान पूजा अपने भाई विवेक तिवारी को संजय साकेत बनाकर समीर के सामने लाई थी। विवेक ने संजय साकेत के नाम से हस्ताक्षर भी किए थे। हैरानी की बात ये है कि जिस संजय साकेत के नाम पर कार खरीदी गई गई उसे खुद इसका पता तब चला जब फाइनेंस कंपनी के बाउंसर उसके पास पहुंचे जिसके बाद उसने भी पुलिस में शिकायत की थी।

भारतीय मानवाधिकार एसोसियेशन की एक महत्वपूर्ण बैठक आज नेहरु नगर स्थित योग आश्रम में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक का उद्देश्य समाज के अतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक मानवाधिकारों की प्रभावी पहुँच सुनिश्चित करना तथा योग और नैतिक मूल्यों के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था।



टीएल बैठक में निगम आयुक्त ने जताई सरख्ती

अवैध कॉलोनियों व जनसमस्याओं पर दिए कड़े निर्देश

रीवा। नगर निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे द्वारा दिनांक 23 जून को निगम सभागार में विभागीय टीएल बैठक आयोजित की गई। बैठक में लॉबित टीएल पत्रों, अवैध कॉलोनियों, जल गंगा संवर्धन, माई रीवा सिटीजन ऐप एवं सोशल मीडिया से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। निगमायुक्त ने साई मंदिर के पास भिक्षावृत्ति कर रहे व्यक्तियों का सर्वे कर सूची तैयार करने एवं जिनके पास परिवार व निवास है, उन्हें वहां भेजने तथा भरण-पोषण नियम के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शेष लोगों पर सामाजिक न्याय व राजस्व विभाग के समन्वय से कार्यवाही करने को कहा। सार्वजनिक संपत्ति में छेड़छाड़ हेतु संपत्ति विरूपण एवं अवैध वॉल पेंटिंग इत्यादि पर आउटडोर नियम के तहत कार्यवाही करें। कहीं भी कुछ भी पेंट करने वालों



एवं बिलबोर्ड पेस्ट कर शहर की सुंदरता से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। वार्ड 15 की मुक्तिधाम योजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही जोन ऑफिस का प्लान तैयार करने को कहा। नालियों के सही से इंटरलॉकिंग न होने एवं जलप्लावन की समस्या पर कहा कि अन्य निर्माण एजेंसी से भी

समन्वय कर नाली कार्य का सुपरविजन सुनिश्चित करें क्योंकि शहर में पानी निकासी की समस्या पर नगर निगम को कार्य करना पड़ता है। आवारा पशुओं की शिकायत पर कहा कि अभियान चलाकर उन्हें पकड़ने की कार्यवाही करें एवं ऐसा छोड़ने वालों के पशुओं को जब्त कर कार्यवाही करें। सब्जी मंडी की

अव्यवस्था पर कहा कि छोटे फुटकर दुकानों के लिए स्थल चिन्हित कर जोनवार शिफ्ट करने की योजना बनाए, जिससे पुरानी सब्जी मंडी की व्यास समस्या से निजात मिल सके एवं छोटे दुकानदारों की व्यवस्था भी हो सके। नाले पर अतिक्रमण पर सख्त निर्देश दिए कि नाले का सीमांकन कराकर नियमानुसार कार्यवाही करें। वर्षा ऋतु में सूखे गिरने की हालत में आए वृक्षों को चिन्हित कर हटाने के निर्देश दिए एवं जर्जर भवन चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। अवैध कॉलोनी की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि 2016 के पूर्व सार्वजनिक भूमि रिक्त न छोड़ने वाली कॉलोनियों के दावा-आपत्ति के बाद नियमानुसार वसूली अधिरोपित करने के निर्देश दिए गए। चिन्हित अवैध कॉलोनी पर सख्ती के साथ ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के निर्देश दिए गए एवं जोन 3 में

अपेक्षित एफआईआर की कार्यवाही न होने पर ईई एवं सहायक यंत्री को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी अवैध कॉलोनी छूटनी नहीं चाहिए, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही निर्देशित किया कि जिनकी अनावश्यक 1 महीने से अधिक टीएल पत्र लॉबित होती है, उनकी एक वेतनवृद्धि रोकी जाए। बैठक के दौरान कार्यपालन यंत्री श्री राजेश सिंह, श्री एचके त्रिपाठी, उपायुक्त श्री प्रकाश द्विवेदी, श्री एमएस सिद्दीकी, सहायक आयुक्त श्री रामनरेश तिवारी, सुश्री शीतल भलावी, सहायक यंत्री श्री एसके गर्ग, श्री अम्बरीश सिंह, श्री राजेश मिश्रा, श्री पीएन शुक्ला, श्री अभिनव चतुर्वेदी, स्वास्थ्य अधिकारी श्री मुरारी कुमार, सहायक राजस्व अधिकारी श्री रावेंद्र सिंह, श्री नीलेश चतुर्वेदी एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

मिट्टी के पोषक तत्व और गुण बताता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड

रीवा। भारत सरकार द्वारा स्वाइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत किसान सिंचित क्षेत्र में 2.5 एकड़ तथा अंसिंचित क्षेत्र में 10 एकड़ क्षेत्र से मिट्टी का नमूना लेकर उसकी जाँच कराते हैं। यह जाँच कृषि विभाग द्वारा की जाती है। कृषि विभाग द्वारा मिट्टी के नमूने लिए जाने पर इसकी जाँच पूरी तरह से निशुल्क रहती है। यदि किसान स्वयं सेंपल लेकर जाता है तो मिट्टी के नमूने की जाँच के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के किसान को तीन रुपए तथा सामान्य वर्ग

के किसान को पाँच रुपए प्रति नमूना शुल्क देना होता है। मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रेंट की जाँच कराने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को 30 रुपए तथा सामान्य वर्ग के किसानों को 40 रुपए शुल्क देना होता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किसान को उसके खेती की मिट्टी के गुणों तथा पोषक तत्वों की जानकारी मिलती है। इस संबंध में उप संचालक कृषि यूपी बागरी ने बताया कि मिट्टी के पोषक तत्व के आधार पर किसान को उचित फसल की सलाह दी जाती है। मिट्टी में यदि पोषक तत्व की कमी है तो

उसके अनुरूप उर्वरक के उपयोग का सुझाव दिया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसान के खेत की मिट्टी का रिपोर्ट कार्ड है। इस कार्ड में किसान का नाम, सर्वे नम्बर, खेत का रकबा आदि लिखा रहता है। प्रत्येक तीन साल में मिट्टी की जाँच कराकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दर्ज कराना आवश्यक है। हर किसान अपने प्रत्येक खेत की मिट्टी की जाँच कराकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड अवश्य बनवाएं। इससे सही फसल के चयन, खाद के संतुलित उपयोग और जल प्रदूषण से बचाव में सहायता मिलती है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

रीवा। जिले के विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया में हो रही अनियमितताओं और छात्रों को हो रही समस्याओं के विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रीवा नगर इकाई ने जिला शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि कुछ विद्यालय मनमानी फीस वसूल रहे हैं और पात्र छात्रों को प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। इसके अलावा, कई स्कूलों में आरक्षित वर्ग के छात्रों को नियमों के अनुसार प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जिससे अभिभावकों और छात्रों में भारी असंतोष है। ज्ञापन सौंपते समय परिषद के नगर मंत्री हर्ष साहू



ने कहा, शिक्षा का अधिकार सभी छात्रों का मौलिक अधिकार है। यदि विद्यालयों द्वारा मनमानी की जाती रही तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन के लिए बाध्य होगी। तथा इसकी पूर्ण

जवाबदारी प्रसासन की होगी। उन्होंने कहा कि कुछ विद्यालयों में बिना किसी नियम या पारदर्शिता के छात्रों से पैसे लेकर प्रवेश दिया जा रहा है, जो पूरी तरह से अनुचित और

भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है।

हर्ष साहू ने कहा कि शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। सरकारी या सहायता प्राप्त विद्यालयों में पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ही दाखिले होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में कई मामलों में देखा गया है कि प्रबंधन पैसे लेकर छात्रों को प्राथमिकता दे रहा है। इससे मेधावी व आर्थिक रूप से कमजोर छात्र पीछे छूट रहे हैं।

एबीवीपी के जिला संयोजक पी एन पांडे ने बताया कि कई विद्यालयों में अभी तक पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि संबंधित

विभाग जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरे और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए।

जिला शिक्षा अधिकारी ने ज्ञापन प्राप्त कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया और संबंधित विद्यालयों से स्पष्टीकरण मांगा जाने की बात कही।

ज्ञापन सौंपने में प्रमुख रूप से जिला संयोजक पी एन पांडे, विभाग ज्ञापक प्रमुख कृति तिवारी, नगर मंत्री हर्ष साहू, वि वि मंत्री लव पांडे,आयुष शुक्ला,आशीष द्विवेदी, अनुराग द्विवेदी, शशांक, देवांशी, विनय गौतम, ओमकार जायसवाल , शिवेश आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

मऊगंज में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित

मऊगंज। मऊगंज जिले में वर्षाकाल के दौरान जल भराव, पानी निकासी, बाढ़ की स्थित पर निगरानी रखने तथा राहत एवं सहायता तथा बाढ़ राहत प्रबंधन हेतु जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट मऊगंज में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यह नियंत्रण कक्ष 24 घंटे काम करेंगा। बाढ़ नियंत्रण कक्ष का प्रभारी संयुक्त कलेक्टर राजेश मेहता को बनाया गया है। उनका मोबाइल नंबर 9993887923 है।

इसके साथ ही सहायक प्रभारी अधिकारी शिवप्रसाद नामदेव सहायक अधीक्षक भूअभिलेख होंगें जिनका मोबाइल नंबर 9329319981 है तथा इनके सहयोग के लिए अमित कुमार नामदेव कम्प्यूटर आपरेटर मोबाइल नंबर 7240898979 को नियुक्त किया गया है। कलेक्टर संजय कुमार जैन ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष में सुबह की पाली में प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक सौरभ मिश्रा

मोबाइल नंबर 9302771971 एवं रामजी तिवारी मोबाइल नंबर 9201027597 को नियुक्त किया है। जबकि दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रेमप्रकाश मिश्रा मोबाइल नंबर 9755114666 तथा अव्यत अवधिया मोबाइल नंबर 9098085219 की ड्यूटी लगायी है। इसी प्रकार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक भानू प्रताप सिंह मोबाइल नंबर 9977528094 एवं मिथिलेश प्रसाद तिवारी मोबाइल

नंबर 920353261 को नियुक्त किया गया है। रिजर्व के तौर पर मुन्नालाल साकेत मोबाइल नंबर 9752862336 तथा सुनील प्रताप सिंह मोबाइल नंबर 8461803880 एवं वीरेंद्र कुमार मिश्रा मोबाइल नंबर 9553385226 को रखा गया है।

कलेक्टर ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष में दैनिक जानकारी पंजी में संधारित कर अपर कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर को प्रेषित करने के निर्देश दिये हैं।

स्वीप गतिविधियों का सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार के निर्देश

रीवा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी स्वीप गतिविधियों का सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किये जाने के निर्देश दिये हैं। उप मुख्यमंत्री निर्वाचन पदाधिकारी ने जिले में होने वाली निर्वाचन संबंधी समस्त गतिविधियों का प्रिंट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जिला स्तर पर प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिये हैं।

भाजपा की सरकार ने पूरा किया डॉ. मुखर्जी का संकल्प: राजेंद्र

मऊगंज। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ राजेंद्र मिश्रा ने खटखरी मंडल के बूथ क्रमांक 197 में कार्यकर्ताओं के साथ बलिदान दिवस में उपस्थित हुए उन्होंनेडॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुण्य स्मरण करते हुएकहा कि डॉ. मुखर्जी ने धारा 370 के खिलाफ आंदोलन किया, जिसके चलते उन्हें जेल भेज दिया गया और जेल में ही डॉ. मुखर्जी की हत्या कर दी गई।

मऊगंज के सभी मतदान केन्द्रों में वृक्षारोपण के साथ मनाया गया बलिदान दिवस

श्री शर्मा ने कहा कि श्रद्धेय अटलजी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, लेकिन पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं था, इसलिए धारा 370 को हटाना नहीं जा सका। जब 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में

सरकार बनी, जब धारा 370 हटाने को लेकर संसद में बहस चल रही थी, तब कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों ने कहा था कि अगर धारा 370 हटाई गई, तो देश टूट जाएगा, कश्मीर जल जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने धारा 370 हटा दी। उन्होंने कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं

भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजनानर्तगत रीवा जिले के लिये लक्ष्य आवंटित

रीवा। भगवान बिरसामुण्डा स्वरोजगार योजना एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के लिये जिले का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। जिला संयोजक अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार भगवान बिरसा मुण्डा योजना के लिये 15 तथा टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के लिये 78 प्रकरणों का लक्ष्य नियत किया गया है। जिले के बैंकों के लिये लक्ष्य का पुनर्वहन कर ऋण प्रकरणों की समय सीमा में स्वीकृति जारी करने की अपेक्षा बैंक से की गई है। भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना में उद्योग इकाई विनिर्माण हेतु एक लाख से 50 लाख की परियोजनाएं एवं सेवा इकाई व खुदरा व्यवसाय हेतु एक लाख रूप्ये से 25 लाख तक की परियोजनाएं एवं 5

प्रतिशत व्याज अनुदान 7 वर्ष तक निवर्तित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर त्रैमासिक दिया जायेगा। गारंटी फीस म.प्र. शासन द्वारा देय होगी। इसके लिये आवेदक जिले का निवासी हो, आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आवेदक की उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य हो, आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो। आवेदक स्वयं किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो। पात्रता धारी आवेदक एमपी आनलाइन के पोर्टल के माध्यम से उक्त योजनाओं में आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय कलेक्टर जनजातीय कार्य विभाग रीवा में संपर्क किया जा सकता है।

रोजगार परक शिक्षा हेतु एमसीयू में पढ़ाई सर्वश्रेष्ठ विकल्प : शुक्ल

रीवा। मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने इस बात पर जोर दिया कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षा के साथ-साथ छात्रों के लिए सौ प्रतिशत प्लेसमेंट की दिशा में प्रयास करें। रीवा परिसर में पठन-पाठन की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि यह युग मीडिया व जनसंचार का है और इस क्षेत्र में मेधावी छात्रों के लिए अकूत संभावनाएं हैं। विश्वविद्यालय का रीवा परिसर शिक्षण संस्थाओं की अधोसंरचना व संसाधनों की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रकल्प है। इस संस्थान का ज्यादा से ज्यादा लाभ विद्यार्थियों मिलना चाहिए। उपमुख्यमंत्री श्री शुक्ला ने रीवा परिसर की



अत्याधुनिक टीवी स्क्रीन शोष्र ही प्रारंभ होने वाले रेडियो कर्मचारी के बारे में जानकारी ली। विश्वविद्यालय के एडजुक्ट प्रोफेसर एवं वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर जयराम शुक्ल ने उपमुख्यमंत्री श्री शुक्ला

को यहां संचालित किए जा रहे सभी पाठ्यक्रमों की जानकारी दी। श्री शुक्ला ने बताया कि माखनलाल विश्वविद्यालय के स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की विशेषता यह है कि यहां के

छात्र यदि पत्रकारिता व जनसंचार से इतर भी अपना कोई करियर चुनना चाहते हैं तो मध्यप्रदेश व देश की पीएससी, यूपीएससी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। पत्रकारिता व

जनसंचार की शिक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान की दृष्टि से और भी उपयोगी होगी। श्री शुक्ला ने कहा जो छात्र बीए, बीएससी बीकॉम पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बीए (जनसंचार) बीएससी (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) बीसीए, एमए (जनसंचार) एमए (पत्रकारिता), एमएससी (इलेक्ट्रानिक मीडिया) जैसे कोर्स बेहतर विकल्प हैं। इसी तरह किसी भी विषय के स्नातक, माखनलाल विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को अपनाकर अपना करियर विशिष्ट बना सकते हैं।

विश्वविद्यालय के रीवा परिसर के निदेशक डॉ.संतेंद्र डेहरिया ने इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री जी को जानकारी दी कि विश्वविद्यालय में प्रवेश की तिथि 10 जुलाई तक बढ़ाई गई है।

डॉ. डेहरिया ने बताया कि हम शोष्र ही बीबीए और एमबीए पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। विषय विशेषज्ञों की अंतिम स्वीकृति के बाद अगले सत्र से यह पाठ्यक्रम शुरू होने की संभावना है। ग्रामीण जनसंचार की जरूरत को देखते हुए शोष्र ही विश्वविद्यालय का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो कर्मचारी आन एयर होगा।

सहायक कुलसचिव प्रशासन विवेक शाक्य ने इस अवसर पर जानकारी दी कि परिसर के विस्तार स्वरूप गलर्स हॉस्टल जिम्मेजियम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। छात्रों की सुविधा हेतु सुव्यवस्थित कैटिन का शुभारंभ इसी सत्र से प्रारंभ कर दिया जाएगा विश्वविद्यालय में 24 जुलाई को व्यापक स्तर पर हरियाली महोत्सव मनाया जाएगा।